3 औषधि विक्रेता संघ ने हड़ताल का ज्ञापन सौपा

5 सिद्धांत, सादगी और सत्यनिष्ठा के प्रतीक

7 नेपाल की क्रांतिः लोकतंत्र के लिए विनाशक

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 23 प्रति सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, मासूमों की मौतों ने झकझोरा जनविश्वास

मासूम के परिजनों को मिले जख्म, प्रदेश की भाजपा सरकार को पड़ सकता है महंगा

कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर कटघरे में है। मछली कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौतों ने प्रदेश की जनता को स्तब्ध कर दिया है। इस त्रासदी ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिंह लगाया है, बल्कि शासन-प्रशासन की निगरानी और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित अन्य हिस्सों में बीमार बच्चों के इलाज के दौरान संदिग्ध कफ सिरप के उपयोग से 24 से अधिक मासूमों की मौत की खबरों ने लोगों के दिलों को दहला दिया है। अस्पतालों में भर्ती कई बच्चे अब भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। प्रारंभिक जांचों में यह संकेत मिला है

कि जिस दवा का उपयोग किया गया, वह पर्याप्त क्लीनिकल ट्रायल और गुणवत्ता परीक्षण से नहीं गुजरी थी। यह स्थिति राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में व्याप्त नियामक शिथिलाई और लापरवाही की ओर इशारा करती है। किसी भी दवा को सार्वजनिक उपयोग से पहले कठोर परीक्षण और वैधानिक स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन यहाँ प्रतीत होता है कि या तो वह प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई या फिर उसकी उपेक्षा हुई।

प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की कमी

किसी भी राज्य की दवा नियंत्रण प्रणाली में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक दायित्व होता है कि हर दवा सुरक्षित और मानक अनुरूप हो। मगर यह घटना दर्शाती है कि निगरानी तंत्र न केवल कमजोर पड़ा है, बल्कि संभवतः सप्लाई और स्वीकृति प्रक्रिया में भी पारदर्शिता की कमी रही है। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के दो वर्ष: जनकल्याण, विकास और विश्वास का नया अध्याय

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने की तैयारी में है। इस अवसर पर शासन ने व्यापक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और जनता से मिले भरोसे को सामने लाने की योजना है। इन दो वर्षों में साय सरकार ने न केवल जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यभार संभालने के बाद ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार का लक्ष्य "जनता के विश्वास पर खरा उतरना और छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाना" है। इस दृष्टि से सरकार ने दो वर्षों में ऐसे अनेक निर्णय लिए जिनका सीधा लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचा। इनमें प्रमुख हैं। किसानों के लिए ऋणमाफी और फसल बीमा योजनाओं का सरलीकरण,

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'महिला सुरक्षा मिशन', युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए "गांव विकास अभियान" की शुरुआत। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार, और टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाया है।

जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को लाभ

साय सरकार का दावा है कि दो वर्षों में राज्य के लगभग हर वर्ग तक उसकी योजनाओं का लाभ पहुँचा है। किसान वर्ग को "राजीव कृषि समृद्धि योजना" के माध्यम से समय पर बीज, खाद और समर्थन मूल्य की गारंटी दी गई। महिलाओं के लिए "मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना" ने स्वरोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोले।

जोरों पर छत्तीसगढ़ में ED की कार्रवाही पर ब्रेक लगाने की तिकड़में

700 करोड़ के कोयला घोटाले में IAS और IPS अधिकारियों के बीच अरबों का लेन–देन आया सामने

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के कोल लेव्ही परिवहन घोटाले में उपकृत होने वाले IAS और IPS अधिकारियों का काला चिटठा सामने आया है। जबकि ऐसे प्रभावशील दागी अधिकारियों के खिलाफ बगैर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किये ही मौजूदा चीफ सेकेट्री रिटायर हो गए है। उनकी कार्यप्रणाली से जहाँ भ्रष्टाचार को लगातार संरक्षण प्राप्त हो रहा था, वही अब नए चीफ सेकेट्री के रुख को लेकर मंत्रालय में गहमागहमी देखी जा रही है।

सुर्खियों में रहा IAS-IPS अधिकारियों का काला चिट्ठा

इस बीच प्रदेश के कोल खनन परिवहन घोटाले में लिप्त रायपुर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर के तत्कालीन एसएसपी-कलेक्टर और अन्य अफसरों की संलिप्ता का काला चिटठा सुर्खियों में है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ कैडर के आल इंडिया सर्विस के कतिपय चुनिंदा अधिकारी भूपेश राज में आए दिन करोड़ों की रकम पर हाथ साफ कर रहे थे। उनके लेन–देन का नमूना मात्र देखकर आप रोजाना के अवैध कारोबार का अंदाजा लगा सकते हैं। घोटाले के किंगपिन से इन अफसरों का करीब का नाता बताया जाता है। ये IAS और IPS अधिकारी आपस में सांठगांठ कर छत्तीसगढ़ शासन की तिजोरी को किसी प्रोफेशनल गिरोह की तर्ज पर चूना लगा रहे थे। उनका लेनदेन गंभीर आर्थिक अपराध के दायरे में बताया जाता है। एक IAS अधिकारी ने कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी को 11 करोड़ 05 लाख की नगद रकम की अदायगी की थी, जबकि वर्दीधारी एक प्रभावशील ASP ने इसी कोल माफिया सूर्यकान्त तिवारी से 05 करोड़ 67 लाख की नगदी प्राप्त की थी। इसके अलावा ED ने अन्य IAS-IPS की कार्यप्रणाली से भी मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा पत्र लिखकर महीने भर पहले अवगत कराया था। लेकिन अकार्यकुशल निवर्तमान चीफ सेक्रेटरी ने ED के इस पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। (शेष पेज 6 पर)

मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, मासूमों की मौतों ने झकझोरा जनविश्वास

(पेज 1 का शेष)

मध्यप्रदेश में दवा वितरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में कई स्तरों पर जांच और परीक्षण की व्यवस्था है जैसे फार्मेसी निरीक्षण, दवा परीक्षण प्रयोगशाला और चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्वीकृति प्रणाली। इन सभी के बावजूद अगर संदिग्ध दवा अस्पतालों तक पहुँच गई, तो यह केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की विफलता का संकेत है।

दो मंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक अफसर की भूमिका संदिग्ध

सूत्रों के अनुसार जिस समय कोल्ड्रिफ कफ सिरप की सप्लाई को मध्यप्रदेश में हरी झंडी दी गई थी उस समय में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान थे। यही नहीं शिवराज सिंह चौहान के चहेते अफसर मोहम्मद सुलेमान और मंत्री विश्वास सारंग और डॉ. प्रभुराम चौधरी के ऊपर स्वास्थ्य विभाग की समस्त जिम्मेदारी थी। ऐसे में इन सभी ने बगैर जांच किये आखिर कैसे इस जहरीली दवाई को सप्लाई करने की हरी झंडी दी, यह जांच का विषय है। यही नहीं अगर ऐसा कुछ सच में हुआ है और इन्हीं तीनों से कोई एक जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जनता के सामने स्थिति को सामने लाना होगा और मासूमों की मौत से खिलवाड़ करने वाले शख्स को कड़ी सजा देना चाहिए। कुल मिलाकर दो मंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक अफसर की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध दिखाई पड़ती है।

राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही

किसी भी त्रासदी के बाद सवाल यह उठता है कि जिम्मेदारी तय कौन करेगा? राज्य में वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, जो इसे और गंभीर बनाता है। यदि प्रशासनिक स्तर पर निगरानी कमजोर है, तो उसकी जवाबदेही शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचती है। प्रदेश के पिछले वर्षों में स्वास्थ्य से जुड़े कई विवाद सामने आए ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी, चिकित्सक नियुक्तियों में अनियमितताएँ, और अब कफ सिरप कांड। हर बार जांच की घोषणा होती है, रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन कार्रवाई अक्सर कागजों से आगे नहीं बढ़ती। जनता में यह धारणा बन रही है कि "जांच" सरकार की जिम्मेदारी से बचने का औपचारिक तरीका बन गई है।

जनता की पीड़ा और विश्वास का संकट

इन घटनाओं का सबसे बड़ा असर जनता के विश्वास पर पड़ता है। जब माता-पिता अपने बीमार बच्चों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाते हैं, तो उन्हें भरोसा होता है कि वहाँ दी जाने वाली दवाएँ सुरक्षित हैं। लेकिन जब वही दवा बच्चों की जान ले लेती है, तो यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि विश्वास की हत्या बन जाती है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाएँ पहले से ही सीमित हैं। वहाँ अगर इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं, तो आमजन के मन में सरकारी चिकित्सा संस्थानों के प्रति भय और बढ़ जाता है। इससे न केवल सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता प्रभावित होती है, बल्कि निजी दवा कंपनियों के प्रति अनावश्यक निर्भरता भी बढ़ जाती है।

सिस्टम में सुधार की ज़रूरत

इस त्रासदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासनिक मॉडल की सख्त आवश्यकता है। दवा आपूर्ति से लेकर उपयोग तक की प्रत्येक प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक ढंग से संचालित करना होगा।

दवा अनुमोदन प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन– प्रत्येक दवा को उपयोग की अनुमति देने से पहले स्वतंत्र लैब में परीक्षण और क्लीनिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।

जवाबदेही तय हो– किसी भी लापरवाही पर केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं, बल्कि निर्णय स्तर पर बैठे अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुधार– डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण में दवा की सुरक्षा और नैतिक उपयोग पर विशेष मॉड्यूल जोड़ा जाना चाहिए।

जनसंवाद और पारदर्शिता– सरकार को हर बड़ी स्वास्थ्य घटना की जानकारी जनता से साझा करनी चाहिए ताकि अफवाहों की जगह भरोसा कायम हो।

विकास और जवाबदेही का द्वंद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने कार्यकाल में विकास और सुशासन का नारा दिया है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र की इन घटनाओं ने इस वादे पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। विकास केवल सड़कों, योजनाओं या निवेश से नहीं होता, असली विकास तब होता है जब राज्य का हर नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करे। कफ सिरप कांड केवल एक प्रशासनिक भूल नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अगर व्यवस्था समय रहते नहीं संभली तो इसका दुष्परिणाम आने वाले वर्षों तक प्रदेश की छवि पर पड़ेगा।

अब जवाबदेही तय करने का समय

हर बड़ी त्रासदी हमें एक अवसर देती है सुधार का, आत्ममंथन का। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच कराए, दोषियों को दंडित करे और दवा स्वीकृति प्रणाली में पारदर्शिता लाए। यह समय "जांच के नाम पर राहत" देने का नहीं, बल्कि सत्य और उत्तरदायित्व के मार्ग पर चलने का है। क्योंकि जिन मासूमों ने अपनी जान गंवाई, उनका दोष केवल इतना था कि उन्हें अपने ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा था और यह भरोसा लौटाना अब सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के दो वर्ष:

जनकल्याण, विकास और विश्वास का नया

(पेज 1 का शेष)

युवा वर्ग को "छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन" के तहत स्टार्टअप, प्रशिक्षण और सरकारी नियुक्तियों में नई संभावनाएँ मिलीं। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में "वन संपदा मिशन" और "जन वन योजना" के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला। वृद्धजन और दिव्यांगों के लिए "सुख जीवन पेंशन योजना" का विस्तार कर सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाया गया। इन योजनाओं ने न केवल लोगों के जीवन में सुधार किया, बल्कि राज्य सरकार के प्रति जनता के विश्वास को भी मजबूत किया है।

संवेदनशील शासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में कदम

विष्णुदेव साय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता रही है। संवेदनशील शासन प्रणाली। मुख्यमंत्री ने स्वयं कई बार जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। 'मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम' के तहत साय प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों की शिकायतें सुनते हैं और तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हैं। इस पहल से जनता को प्रशासन से सीधा जुड़ाव मिला है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी सफलता मिली है। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में भी छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है। "ई-सेवा पोर्टल" के माध्यम से अब राज्य की अधिकांश सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को सुविधा मिली है और समय व धन दोनों की बचत हुई है।

आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता और निवेश को बढ़ावा

पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने स्थिरता और पुनर्जीवन के संकेत दिए हैं। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए साय सरकार ने "निवेश मित्र नीति 2024" लागू की, जिसके तहत छोटे और मध्यम उद्योगों को कर रियायतें और तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रणाली अपनाई गई। इससे न केवल राजस्व बढ़ा बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएँ भी कम हुईं। साथ ही, ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में "सूर्य ग्राम" योजना के तहत हजारों घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रगति

शिक्षा के क्षेत्र में "ज्ञान दीप अभियान" के माध्यम से साय सरकार ने विद्यालयों की दशा और शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने का बीड़ा उठाया। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सामग्री की उपलब्धता ने ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा को और आकर्षक बनाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" ने लाखों परिवारों को निःशुल्क उपचार का लाभ दिया। महिला एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए मातृत्व सेवाओं और एम्बुलेंस नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में साय सरकार ने दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएँ शुरू की हैं।

जनता के बीच बढ़ा विश्वास

दो वर्षों में विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्य और नीतियों से जनता का भरोसा जीतने में सफलता पाई है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों को महसूस हुआ है कि शासन अब केवल "कथन" नहीं, बल्कि "क्रियान्वयन" की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विपक्ष भले ही सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाता रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई जिलों में जनकल्याणकारी योजनाओं के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं हर जिले का दौरा कर विकास परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। इससे जनता में यह संदेश गया है कि सरकार जमीन पर उतरकर काम कर रही है।

भविष्य की दिशा: "सबका विकास– सबका विश्वास"

दो वर्ष पूरे होने पर साय सरकार अब अगले तीन वर्षों के लिए "विजन छत्तीसगढ़ 2028" पर काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है। "हमारी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को उनका वास्तविक लाभ मिले। हमारी राजनीति सेवा की राजनीति है।" सरकार के आगामी कार्यक्रमों में "जनसेवा सप्ताह", "कृषि सम्मेलन" और "उद्योग निवेश महोत्सव" जैसे आयोजन शामिल हैं, जिनके माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की योजना है।

जनसेवा से उपजा भरोसा

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के दो वर्ष विकास, पारदर्शिता और संवेदनशील शासन के प्रतीक बनकर उभरे हैं। इन दो वर्षों में राज्य ने जिस तरह आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन देखा है, वह इस बात का संकेत है कि सरकार अपने "जनकल्याण केंद्रित दृष्टिकोण" पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। साय सरकार ने यह साबित किया है कि यदि नीयत साफ हो, नीति ठोस हो और जनता से सीधा संवाद बना रहे, तो विश्वास स्वतः निर्मित होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले तीन वर्षों में यह सरकार अपनी इन उपलब्धियों को और किस ऊँचाई तक ले जा पाती है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि साय सरकार के इन दो वर्षों ने छत्तीसगढ़ के विकास की नई इबारत लिख दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया किसानों के लिए दो नई योजनाओं का शुभारंभ

प्रदेश में खेती-किसानी की तस्वीर बदलेगी और आर्थिक सम्पन्नता आएगी: मुख्यमंत्री श्री साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह से देश के किसानों को 41 हजार करोड़ रूपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया। उन्होंने इस मौके पर दो नई योजनाएं- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए 30 हजार करोड़ रूपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11 हजार करोड़ रूपए शामिल है। इसके अलावा मोदी कृषि और संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार से हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ऑनलाईन जुड़कर इस अभियान के शुभारंभ के साक्षी बने। इस मौके पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद और विधायक भी वर्चुअली रूप से जुड़े थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि "भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के दिन आज देश कृषि आत्मनिर्भरता का नया इतिहास रच रहा है। आज से प्रारंभ हुई दोनों योजनाएं देश के अन्नदाताओं को सशक्त बनाने और कृषि आत्मनिर्भरता के नए युग की शुरुआत है। खेती को लाभकारी और आधुनिक बनाने की दिशा में यह पहल मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में भारत का कृषि निर्यात बढ़ा है, शहद उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन सहित सहायक कृषि गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विकास के पैरामीटर में पिछड़ रहे जिलों के लिए केंद्रित आकांक्षी जिला योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सुधार का काम हुआ है। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत खेती किसानी में पिछड़े देश के 100 जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 36 नई योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा किसानों की भागीदारी से खेती की तस्वीर बदलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों और आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। यह मिशन न केवल कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है, बल्कि देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए हमें मिलकर दलहन उत्पादन की सशक्त व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत अपनी दलहन आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से दाल उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग दो करोड़ दाल उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बड़ी ख़ुशी की बात है कि किसान हित में दो नई योजनाओं में छत्तीसगढ़ के तीन जिलों जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा को भी शामिल किया गया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इन दो नई योजनाओं के लिए प्रदेश के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन योजनाओं से खेती-किसानी की तस्वीर बदलेगी और आर्थिक सम्पन्नता भी आएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और कृषि अभियांत्रिकी सब मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टरों, कृषि उपकरणों की चाबी भी सौपी और अनुदान राशि का चेक प्रदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का बोलबाला है। जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद एक दिन मैं एक ट्रैक्टर शो रूम में गया, यहां आकर मुझे पता चला कि एक ट्रैक्टर के पीछे 40,000 से 60,000 तक की राशि बचत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टॉल देखने के दौरान यहां मुझे एक किसान भाई मिले जिन्होंने हार्वेस्टर खरीदा, उन्हें एक लाख रुपए से भी अधिक की भी बचत का फ़ायदा मिला। यह देखकर बड़ी ख़ुशी होती है कि हमारे किसान भाइयों को इतना फायदा मिल रहा है। साय ने बताया कि सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। किसानों से किया हर वादा हमने पूरा कर दिया है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी, दो साल का बकाया बोनस भुगतान किया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने किसानों को प्राथमिकता में लेते हुए राज्य में 1500 से अधिक सिंचाई योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए एकमुश्त 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि योजनाओं के मजबूतीकरण के लिए कई अहम कार्य हुए। किसान क्रेडिट कार्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सीमांत किसान हैं, उन्हें सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है और यह योजना उसी दिशा में एक ठोस पहल है।

औषधि विक्रेता संघ ने हड़ताल का ज्ञापन सौंपा

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. टेवरीकला। प्रशासन द्वारा एकपक्षीय अनुचित कार्यवाही करने के विरोध में औषधि विक्रेता संघ देवरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि हमारा संगठन जिला औषधि विक्रेता संघ सागर, मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन एवं आल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट (AICDO) से सम्बंधित है, जिसके हम 12.50 लाख सदस्य संपूर्ण भारत में ड्रग एक्ट एवं प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए दवा व्यवसाय करते है। विगत कुछ दिनों से प्रशासन द्वारा तानाशाही तरीके से एकतरफा कार्यवाही की जा रही है, जिससे दवा व्यापारियों के उचित पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। इससे दवा व्यापारी वर्ग छुब्ध एवं नाराज हैं। इन कार्यवाहियों से दवा व्यवसाइयों की छवि धूमिल और साख में धब्बा लग रहा है। जिसके कारण मरीजों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोरोना काल में जब पूरा देश संक्रमण काल से गुजर रहा था उस समय दवा व्यवसाईयों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी निरंतर 24*7 मरीजों को सेवाएं दी थी। उपरोक्त एकपक्षीय कार्यवाही से हमारे व्यापारी वर्ग की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि तत्काल प्रभाव से यह कार्यवाही नहीं रूकती है और सिंघई मेडिकल की दुकान का निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अगर यह निलंबन निरस्त नहीं किया जाता और इस प्रकार की एक पक्षीय कार्यवाही नहीं रूकती है तो हम सभी दवा व्यापारी अनिश्चितकालीन दुकानें बंद करने के लिए मजबूर होंगे। इससे जो भी हानि होती है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में देवरी औषधि विक्रेता संघ अध्यक्ष अमित तिवारी, रामगोपाल बृजपुरिया, मनोज रजक, राजेश प्यासी, कैलाश बृजपुरिया, सुनील जैन, वीरेंद्र उदेनिया, सुधीर जैन, प्रभात सिंघई, शरद सोनी, करण राजपूत, हृदेश हजारी, बंटू ठाकुर, कुलदीप लखेरा, उमेश तिवारी, महेन्द्र सेन, मोनू भारके, सहित बडी संख्या में औषधि विक्रेता संघ के सदस्य मौजूद रहे।

झोलाछाप डाक्टरों पर प्रशासन मौन

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले में प्रतिबंधित कोलड सीरप को लेकर प्रशासन ने तो तत्काल कार्यवाही कर मेडिकल दुकानों की जांचकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन जिला के विकासखंडों में तेजी से फेल रहे झोलाछाप डाक्टरों के नेटवर्क पर अब तक कोई कार्रवाई ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीण अंचलों मे फ़र्जी डाक्टर खुलेआम लोगों को जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ना डिग्री, ना अनुभव, फिर भी ये झोला लटकाए डाक्टर गांव गांव में क्लीनिक खोलकर लोगों को इंजेक्शन और दवा दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना हैं कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी आखें मूदे बैठा है। आए दिन ये झोलाछाप डाक्टर गलत दवाइयों के कारण ग्रामीण लोगों कि सेहत बिगड़ रहे हैं, लेकिन विभागीय ऑफीसर सिर्फ काग़जी जांच और प्रेस नोट तक सीमित हैं। आम जनता का सवाल सीधा हैं जब प्रशासन प्रतिबंधित सिरप पर सख्ती से कार्यवाही की हैं तो बिना डिग्री वाले इन झोलाछाप डाक्टरों पर अब तक कार्यवाही क्यों नही, ग्रामीण अंचलों में खुलेआम यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना हैं कि प्रशासन इस गम्भीर मूद्दे पर नींद से जागेगा या फिर जनता के स्वास्थ्य इसी तरह झोलाछाप डाक्टरों के भरोसे छोड़ दी जाएगी।

सम्पादकीय

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्राः साझेदारी का नया अध्याय

भारत और ब्रिटेन के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की साझा विरासत पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच यह रिश्ता कभी औपनिवेशिक सत्ता के इतिहास से परिभाषित होता था, तो आज यह रिश्ता बराबरी, परस्पर हित और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दो दिवसीय भारत यात्रा इसी बदलते रिश्ते की नई परिभाषा है, जो न केवल कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को नई गति देना है। लंबे समय से चले आ रहे वार्तालापों के बाद अब दोनों देशों ने इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक ऐसा सेतु बनेगा जिससे भारतीय वस्त्र, औषधि, ऑटोमोबाइल, आईटी सेवाएँ और कृषि उत्पाद ब्रिटिश बाजारों में अधिक आसानी से प्रवेश पाएंगे, वहीं ब्रिटेन की उच्च तकनीक, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं को भारत में नया विस्तार मिलेगा। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक दिशा एशियाई देशों की ओर मोड़ी है और भारत इस रणनीति का सबसे केंद्रीय भाग बन चुका है। इस यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि "भारत के बिना ब्रिटेन का वैश्विक आर्थिक भविष्य अधूरा है।" ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने साथ लगभग 125 सदस्यीय व्यापार और औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत आए। यह तथ्य अपने-आप में इस यात्रा के महत्व को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच कई अरब डॉलर के निवेश समझौते हुए हैं, जिनमें ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, रक्षा उत्पादन, शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय उद्योगों के लिए यह अवसर ब्रिटिश पूंजी और तकनीक तक सीधी पहुँच का है, जबकि ब्रिटिश कंपनियाँ भारत के विशाल उपभोक्ता-बाजार और कुशल मानव संसाधन का लाभ उठा सकती हैं। यह "विन-विन" स्थिति दोनों देशों के आर्थिक हितों के अनुरूप है।

21वीं सदी की राजनीति केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। डिजिटल क्षेत्र, साइबर सुरक्षा, रक्षा तकनीक और ऊर्जा नवाचार अब अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के नए स्तंभ हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच इन विषयों पर गहन बातचीत हुई है। रक्षा अनुसंधान, युद्धपोत निर्माण, और संयुक्त अभ्यास जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी है। साथ ही, दोनों देशों ने "हरित ऊर्जा" और "क्लीन टेक्नोलॉजी" में मिलकर काम करने का निर्णय भी लिया है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार होगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि ब्रिटेन ने भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन का संकेत दिया। यह भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और उसकी नीति-निर्माण क्षमता का प्रमाण है। भारत-ब्रिटेन संबंध अब "सहयोगी और समान साझेदारों" के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहाँ एक पक्ष नेतृत्व करता है और दूसरा अनुसरण नहीं करता, बल्कि दोनों मिलकर भविष्य की राह तय करते हैं। भारत और ब्रिटेन को जोड़ने वाली एक और गहरी कड़ी है। प्रवासी भारतीय समुदाय। ब्रिटेन में लगभग 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो वहां की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस यात्रा में प्रवासी भारतीय समुदाय से संवाद भी शामिल था। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी नई पहलें की गईं, जिनमें विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान आदान-प्रदान और कला-संस्कृति परियोजनाएँ शामिल हैं। यह सांस्कृतिक सहयोग केवल सॉफ्ट पावर का प्रतीक नहीं, बल्कि आपसी समझ और विश्वास की नींव को और मजबूत बनाता है।

सियासी गहमागहमी

कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला बना नई चुनौती

छिंदवाड़ा का कफ सिरप अब सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए नहीं, बल्कि सरकार की "राजनीतिक सेहत" के लिए भी खतरा बन गया है। मामला इतना गंभीर है कि अब सवाल सिर्फ दवा के जहर का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की खुराक का भी हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने यह "कफ सिरप केस" एक ऐसी चिकित्सा परीक्षा बन गया है जिसमें न केवल बच्चों की जान का हिसाब देना है, बल्कि शासन की पारदर्शिता का तापमान भी मापना है। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं, "जांच चल रही है।" जांच इतनी चल रही है कि लग रहा है, शायद यही जांच अब राज्य की नई एम्बुलेंस सेवा बन जाएगी। उधर विपक्ष हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में "कफ" को "कफन" में बदलने पर आमादा है। जनता सवाल पूछ रही है कि जब डॉक्टर मुख्यमंत्री हैं तो इलाज क्यों नहीं मिल रहा? कहते हैं, लोकतंत्र में जवाबदेही सर्वोपरि होती है। लेकिन यहाँ जवाबदेही भी शायद खांसी से पीड़ित है। आवाज़ ही नहीं निकल रही। अगर ये मामला यूँ ही सियासत की भाप में उबलता रहा तो डर है कहीं पूरी सरकार को "राजनीतिक खांसी" न लग जाए।

भूपेश बघेल और आयकर की 'राजनीतिक रसीद'

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अब आयकर विभाग वह "पुराना दोस्त" बन गया है जो चुनाव बाद अचानक याद आता है। विभाग के अफसरों ने जैसे ही दस्तक दी, राजनीति में फिर हलचल मच गई। कह रहे हैं, "अब हिसाब किताब होगा!" लेकिन सवाल यह है, ये हिसाब किसका। आमदनी का या आम जनता के धैर्य का? राजनीति में आयकर के नोटिस अब लगभग सम्मान-पत्र बन चुके हैं। पद पर रहते हुए जो "विकास" कहलाता था, पद छोड़ते ही वही "जांच" बन जाता है। बघेल जी भी जानते हैं कि ये केवल टैक्स का मामला नहीं, बल्कि "टाइमिंग" का है। आख़िर जांच एजेंसियों की घड़ी हमेशा सत्ता के साथ ही क्यों चलती है? विपक्ष कह रहा है—यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है। "हम तो केवल फाइल खोल रहे हैं।" जनता सोच रही है—कौन सी फाइल, वो जो बंद नहीं हुई या वो जो कभी थी ही नहीं? अब बघेल जी के लिए राजनीति और आयकर दोनों की परीक्षा साथ-साथ है। फर्क बस इतना है कि एक में वोट गिनने पड़ते हैं, दूसरे में नोट। देखना ये है कि अंत में कौनसा विभाग पास होता है, लोकतंत्र या लेखा-जोखा।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं - इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब - हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज़ कमज़ोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है, और जिसकी ज़िंदगी सस्ती समझी जाती है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से 21 बच्चों की मृत्यु के मामले में अब भी सरकार असंवेदनशील रवैये पर कायम है।

मैंने सरकार से माँग की थी कि सभी मृत बच्चों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। लेकिन अब तक इस माँग पर सरकार ने कार्रवाई करना तो दूर कोई प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं की है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

एके एंटोनी: सिद्धांत, सादगी और सत्यनिष्ठा के प्रतीक

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में ऐसे नेता कम हुए हैं जिन्होंने सत्ता से अधिक सिद्धांत को महत्व दिया और पद से अधिक मूल्य को प्रतिष्ठा दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरक्कपराम्बिल कुरियन एंटोनी का नाम इन्हीं कुछ विरले राजनेताओं में लिया जाता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा और नैतिक आचरण का मार्ग भी हो सकता है। ए.के. एंटोनी का जन्म 28 दिसम्बर 1940 को केरल के अलप्पुझा जिले के चेर्तला कस्बे में एक साधारण लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ। पिता अरक्कपराम्बिल कुरियन पिल्लई का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कठिन हो गई। मां आलेइकट्टी करियन ने कठिन परिस्थितियों में बच्चों का पालन-पोषण किया। एंटोनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा Holy Family Boys High School में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए महाराजा कॉलेज, एरनाकुलम से स्नातक किया। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एरनाकुलम से कानून की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदना और नेतृत्व का गुण दिखने लगा था। एंटोनी ने राजनीति में प्रवेश छात्र आंदोलनों से किया। वे केरल स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के सक्रिय सदस्य रहे और जल्द ही उसकी राज्य इकाई के नेता बने। युवावस्था में ही वे कांग्रेस पार्टी के आदर्शों से गहराई से प्रभावित हुए। केरल की राजनीति में उन्होंने खुद को न केवल संगठनात्मक रूप से सिद्ध किया बल्कि एक सजग, पारदर्शी और नैतिक नेता के रूप में पहचान बनाई। एंटोनी पहली बार 1970 में केरल विधानसभा के लिए चुने गए। मात्र 37 वर्ष की आयु में, वर्ष 1977 में वे पहली बार केरल के मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार वे उस समय भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक थे। उनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने प्रशासनिक ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता को प्राथमिकता दी।

वे कुल तीन बार केरल के मुख्यमंत्री बने- 1977-78, 1995-96 और 2001-04 में। उनके शासनकाल को स्वच्छ प्रशासन, लोकतांत्रिक संवाद और जनहितकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। एंटोनी ने कभी भी राजनीतिक समझौते की कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उन्होंने स्वयं पद त्यागने में संकोच नहीं किया। यह उनकी नैतिकता का प्रमाण है।

राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए एंटोनी ने राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कांग्रेस संगठन में कई बार केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (KPCC) के अध्यक्ष रहे और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के महासचिव बने। उनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर गांधी परिवार, के प्रति निष्ठा और सादगी का उदाहरण रहा। वे पार्टी में संतुलन बनाए रखने वाले, मतभेदों को संवाद से सुलझाने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं।

एंटोनी ने केंद्र सरकार में भी कई जिम्मेदारियां संभालीं, परंतु उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका रही भारत के रक्षा मंत्री के रूप में। उन्होंने 2006 से 2014 तक रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व किया जो इस पद पर किसी भी व्यक्ति का सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की सैन्य नीति को पारदर्शिता और स्वदेशीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने रक्षा सौदों में पारदर्शिता सुनिश्चित की और भ्रष्टाचार-विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि कुछ आलोचक उन्हें निर्णय-प्रक्रिया में "अति सतर्क" बताते हैं, लेकिन इस सतर्कता ने उनकी ईमानदार छवि को और सुदृढ़ किया। ए. के. एंटोनी को अक्सर "भारतीय राजनीति का संत" कहा जाता है। वे न तो दिखावे में विश्वास रखते हैं, न विलासिता में। उन्होंने कभी अपना व्यक्तिगत घर नहीं बनाया, वर्षों तक सरकारी आवास में साधारण जीवन व्यतीत किया। उनके वस्त्र-आचरण में सादगी और जीवन-दृष्टि में संयम झलकता है। उनका सार्वजनिक जीवन इस विश्वास पर टिका रहा कि "राजनीति का मूल धर्म जनता की सेवा है।" वे कहते हैं- "सत्ता अस्थायी है, लेकिन ईमानदारी स्थायी मूल्य है।" अपने लंबे राजनीतिक करियर में एंटोनी ने कई कठिन निर्णय लिए। इमरजेंसी के समय उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से असहमति जताई और जनता के प्रति जवाबदेही की मांग की। बाद में उन्होंने कांग्रेस (A) नामक एक अलग राजनीतिक गुट बनाया, परंतु पुनः कांग्रेस में लौटकर संगठन की एकता को प्राथमिकता दी। वे हर परिस्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित के पक्षधर रहे। व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उनकी छवि अखंड ईमानदारी और नैतिक स्थिरता की रही।

करवा चौथः रिश्ते की गहराई का जीवंत महाकाव्य

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

जीवन की तेज़ बहती धारा में जहां करियर की प्रतिस्पर्धा, तकनीकी व्यस्तता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मानवीय संवेदनाओं पर हावी हो रही हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो समय की हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। इन रिश्तों में सबसे पवित्र और अनमोल है पति-पत्नी का संबंध एक ऐसा बंधन जिसे "जीवनसाथी" शब्द अपने आप में पूर्ण कर देता है। इसी रिश्ते की गहराई, अटूट विश्वास और निस्वार्थ समर्पण को समर्पित एक पर्व है - करवा चौथ। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का वह दर्पण है जिसमें दांपत्य जीवन की सबसे सुंदर छवि दिखाई देती है।

आस्था और प्रेम की सदियों पुरानी परंपरा

पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जन्मा यह पर्व आज अपनी भावनात्मक शक्ति के कारण पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुका है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह उत्सव इस वर्ष 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं।

यह व्रत स्वयं में एक कठिन तपस्या है

अन्न और जल का त्याग कर महिलाएं अपने पति के प्रति अपने प्रेम और प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करती हैं। दिन भर के इंतज़ार के बाद छलनी की ओट से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान का जीवंत प्रतीक बन जाता है। पति के हाथ से जल का पहला घूंट ग्रहण करना उस समर्पण को पूर्णता देता है, जो शब्दों से परे केवल महसूस किया जा सकता है।

रिश्तों को जोड़ता भावनात्मक सेतु

आधुनिकता ने जीवन को सरल ज़रूर बनाया है, लेकिन इसके साथ ही रिश्तों में अनकही दूरियां भी बढ़ी हैं। संवाद की जगह सोशल मीडिया ने और साथ बैठने की जगह व्यक्तिगत स्क्रीन ने ले ली है। संयुक्त परिवारों से निकलकर जब रिश्ते एकल परिवारों में सिमट गए हैं, तब करवा चौथ जैसे पर्व रिश्तों को दोबारा जोड़ने वाले भावनात्मक पुल बनते हैं। यह पर्व पति-पत्नी को उनकी व्यस्त दिनचर्या से निकालकर एक-दूसरे के लिए समय निकालने का अवसर देता है। यह दांपत्य जीवन में आए ठहराव को तोड़ता है और रिश्तों में भावनात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह वह दिन होता है जब दोनों एक-दूसरे के त्याग और महत्व को न केवल समझते हैं, बल्कि सम्मान भी देते हैं।

बदलते समय के साथ परंपरा का स्वरूप

करवा चौथ की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी प्रासंगिकता है। यह समय के साथ और गहरी होती गई है। अब यह केवल महिलाओं के त्याग का पर्व नहीं रहा, बल्कि आपसी साझेदारी और सम्मान का उत्सव बन चुका है। अब कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ यह व्रत रखते हैं, यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और सम्मान किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दोनों की साझा भागीदारी है। जब पति भी वही व्रत रखता है जो पत्नी सदियों से निभाती आ रही है, तो यह रिश्ता केवल औपचारिक न रहकर सच्ची समानता और दोस्ती पर आधारित हो जाता है।

सिर्फ रस्म नहीं, भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति

त्योहारों की आत्मा रस्मों में नहीं, उनमें छिपी भावनाओं में बसती है। करवा चौथ का हर रिवाज अपने आप में एक प्रतीकात्मक अर्थ समेटे है:

सरगी: भोर से पहले सास द्वारा बहू को दिया गया भोजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच स्नेह और आशीर्वाद का बंधन है।

सोलह श्रृंगार: सजना-संवरना केवल सौंदर्य नहीं, दांपत्य जीवन के उल्लास और उत्सव की भावना का प्रतीक है।

शाम की कथा: महिलाओं का एक साथ कथा सुनना और पूजा करना सामाजिक एकजुटता और साझे अनुभवों को बांटने का माध्यम है।

चंद्रमा को अर्घ्य: छलनी से चांद और पति को देखना मानो जीवन से दोषों को छानकर केवल पवित्रता और प्रेम को देखना है।

रिश्तों की नींव को सींचता एक उत्सव

करवा चौथ केवल एक व्रत या पर्व नहीं है- यह एक भावना, एक विश्वास और एक संकल्प है। यह पति-पत्नी के बीच प्रेम, त्याग, संवाद और भरोसे की नींव को और भी गहराता है। जब आज के दौर में रिश्ते अक्सर क्षणिक और उथले होते जा रहे हैं, करवा चौथ हमें रिश्तों की गहराई और स्थायित्व का महत्व समझाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि छोटी-छोटी निष्ठाओं, आपसी सम्मान और निस्वार्थ प्रेम की ज़रूरत होती है।

जहरीली दवा बनी अभिशाप

-प्रमोद भार्गव

मध्यप्रदेश और राजस्थान में सर्दी-खांसी की दवा के सेवन से 16 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सीरप स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया गया था, किंतु वह मौत का कारण बन गया। इसकी गुणवत्ता संदेह के दायरे में है। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं दवा नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य ने कहा है कि संदिग्ध सिरप को परीक्षण के लिए 1 अक्टूबर को तमिलनाडु भेजा था। इसकी रिपोर्ट तीसरे दिन मिल गई थी। किंतु मप्र में 29 सितंबर से जांच जारी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। जबकि इसी बीच स्वास्थ्य विभाग का कार्य देख रहे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सार्वजनिक बयान दे दिया कि सीरप के नौ नमूनों में हानिकारक तत्व नहीं मिले हैं। यह सीरप श्रीसन कंपनी बनाती है, जिसकी उत्पादन इकाई तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। मप्र सरकार के कहने पर तमिलनाडु सरकार के औषधि प्रशासन विभाग ने कंपनी की उत्पादन इकाई से नमूने लेकर जांच की तो एसआर-13 बैच में हानिकारक रसायन डायथिलीन ग्लायकल (डीईजी) पाया गया। दवा में इसकी निर्धारित मात्रा 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि इसका प्रतिशत जांच में 48 प्रतिशत से अधिक पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार सक्रिय हुई और इसके उपयोग एवं विक्रय पर रोक लगा दी। मृतक बल-गोपालों का इलाज करने वाले छिंदवाड़ा के चिकित्सक डॉ प्रवीण सोनी पर मामला दर्ज करके,उन्हें फ़िलहाल जमानत पर रिहा कर दिया है। इन मौतों और इस रिपोर्ट के बाद सतर्कता बरतते हुए कई राज्य सरकारों ने इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी सलाह दी है कि दो वर्ष से छोटे बच्चों को कफ सीरप नहीं पिलाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया से लगता है कि प्रदेश में ही नहीं देश में निगरानी तंत्र कमजोर है।

यूपीए सरकार ने जब नकली दवाओं से छुटकारे के नजरिए से औषधीय एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम बनाया था तब यह मान लिया गया था कि अब नकली दवाओं पर कमोबेश प्रतिबंध लग जाएगा। क्योंकि इस कानून के तहत न केवल इस धंधे को गैर जमानती बना दिया गया था, बल्कि दवा बनाने वालों से लेकर बेचने वालों तक को दस साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया था। लेकिन देखने में आया है कि दवा दुकानों पर लगातार नकली दवाओं के भण्डार बरामद हो रहे हैं और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। साफ है, नकली दवा कारोबार न केवल बेखौफ जारी है बल्कि इसमें बेइंतहा इजाफा भी हो रहा है। यही नहीं ये दवाएं सरकारी अस्पतालों के माध्यम से भी धड़ल्ले से उपयोग में लाई जा रही हैं। इससे जाहिर होता है कि सरकारी चिकित्सा-तंत्र का एक बड़ा हिस्सा इस कारोबार को ताकत दे रहा है।

इसके पहले 2019-20 में जम्मू के रामनगर में भी एक फार्मा कंपनी के बनाए सीरप से 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। कंपनी पर एफआईआर हुई, लेकिन मामला अभी भी लंबित है।

वर्श 2022 में हरियाणा की दवा कंपनी के सीरप से गांबिया में 70 और उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों की मौतें हो गई थीं। सितंबर 2008 में भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी रैनबैक्सी की तीस जेनेरिक दवाओं को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था। रैनबैक्सी की देवास (मध्य प्रदेश) और पांवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश) में बनने वाली दवाओं के आयात पर अमेरिका ने रोक लगाई थी। अमेरिका की सरकारी संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) का दावा था कि रैनबैक्सी की भारतीय इकाइयों से जिन दवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका मानक स्तर अमेरिका में बनने वाली दवाओं से घटिया है। ये दवाएं अमेरिकी दवा आचार संहिता की कसौटी पर भी खरी नहीं उतरी थीं। जबकि भारत की रैनबैक्सी ऐसी दवा कंपनी है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाओं का निर्यात करती है। रैनबैक्सी एक साल में कई हजार करोड़ की दवाएं देश व दुनिया में बेचती है। ऐसी ही बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी आचार संहिता के पालन के पक्ष में नहीं हैं। किसी बाध्यकारी कानून को अमल में लाने में भी ये रोड़ा अटकाने का काम करती हैं। क्योंकि ये अपना कारोबार विज्ञापनों व चिकित्सकों को मुनाफा देकर ही फैलाये हुए हैं। छोटी दवा कंपनियों के संघ का तो यहां तक कहना है कि चिकित्सकों को उपहार देने की कुप्रथा पर कानूनी तौर से रोक लग जाए तो दवाओं की कीमतें 50 फीसदी तक कम हो जाएंगी। चूंकि दवा का निर्माण एक विशेष तकनीक के तहत किया जाता है और रोग व दवा विशेषज्ञ चिकित्सक ही पर्चे पर एक निश्चित दवा लेने को कहते हैं। दरअसल इस तथ्य की पृष्ठभूमि में यह मकसद अंतर्निहित है कि रोगी और उसके अभिभावक दवाओं में विलय रसायनों के असर व अनुपात से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए वे दवा अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इस कारण चिकित्सक की लिखी दवा लेना जरूरी होती है।

इंसान की जीवन-रक्षा से जुड़ा दवा करोबार अपने देश में तेजी से मुनाफे की अमानवीय व अनैतिक हवस में बदलता जा रहा है। चिकित्सकों को महंगे उपहार देकर रोगियों के लिए मंहगी और गैर जरुरी दवाएं लिखवाने का प्रचलन लाभ का धंधा हो गया है। इस गोरखधंधे पर लगाम लगाने के नजरिये से कुछ समय पहले केन्द्र सरकार ने दवा कंपनियों से ही एक आचार संहिता लागू कर उसे कड़ाई से अमल में लाने की अपील की थी। लेकिन संहिता का जो स्वरूप सामने लाया गया, वह राहत देने वाला नहीं था। संहिता में चिकित्सकों को उपहार व रिश्वत देकर न तो अनैतिक कारगुजारियों को लेकर कोई साफगोई है और न ही संहिता की प्रस्तावित शर्तें व कानून बाध्यकारी हैं। इन प्रस्तावों को लेकर दवा संघों में भी मतभेद हैं।

विज्ञान की प्रगति और उपलब्धियों के सरोकार आदमी और समाज के हितों में निहित हैं। लेकिन हमारे देश में मुक्त बाजार की उदारवादी व्यवस्था के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जब आगमन हुआ, तो उसके तहं जिस तेजी से व्यक्तिगत व व्यवसायजन्य अर्थ-लिप्सा और लूटतंत्र का विस्तार हुआ है, उसके शिकार चिकित्सक तो हुए ही, निगरानी तंत्र भी इसकी चपेट में है। नतीजतन देखते-देखते भारत के दवा बाजार में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की 70 प्रतिशत से भी ज्यादा की भागीदारी हो गई। इनमें से 25 फीसदी दवा कंपनियां ऐसी हैं जिन पर व्यवसायजन्य अनैतिकता अपनाने के कारण अमेरिका भारी आर्थिक दण्ड दे चुका है।

ऐसे हालात में चिकित्सक अनैतिकता और दवा कंपनियां केवल लाभ का दृष्टिकोण अपनाएंगी तो आर्थिक रूप से कमजोर तबका तो स्वास्थ्य चिकित्सा से बाहर होगा ही, जो मरीज दवा ले रहे हैं उनके मर्ज की दवा सटीक दी जा रही है अथवा नहीं इसकी गारंटी भी नहीं रह जाएगी? इस कारण सरकार ने 2009 के आरंभ में दवा कंपनियों के संघ से स्वयं एक आचार संहिता बनाकर अपनाने को कहा था। साथ ही सरकार ने यह हिदायत भी दी थी कि यदि कंपनियां इस अवैध गोरखधंधे पर अंकुश नहीं लगातीं तो सरकार को इस बाबत कड़ा कानून लाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

लेकिन सरकारी चेतावनी की परवाह किए बिना दवा कंपनियों का संघ जो नई आचार संहिता सामने लाया, उसमें उपहार के रूप में लाभ देने का केवल तरीका बदला गया। मसलन तोहफों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। संहिता में केवल दवा निर्माताओं से उम्मीद जताई गई है कि वे चिकित्सकों को टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, सीडी, डीवीडी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व नकद राशि नहीं देंगे। लेकिन वैज्ञानिक सम्मेलन, कार्यशालाओं और परिचर्चाओं के बहाने उपहार देने का सिलसिला और चिकित्सकों की विदेश यात्राएं जारी रहेंगी। जाहिर है आचार संहिता के बहाने चिकित्सक और उनके परिजनों को विदेश यात्रा की सुविधा को परंपरा बनाने का फरेब संहिता में जानबूझकर डाला गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि भारत में बनने वाली दवाएं करीब 35 प्रतिशत नकली होती हैं। एसोचेम के मुताबिक देश में 25 प्रतिशत की दर से हर साल इस कारोबार में इजाफा हो रहा है। बहरहाल भारत सरकार को दवाओं पर निगरानी के लिए मजबूत तंत्र खड़ा करने की जरूरत है।

700 करोड़ के कोयला घोटाले में IAS और IPS अधिकारियों के बीच अरबों का लेन–देन आया सामने

(पेज 1 का शेष)

शिकायती जांच पत्र को लेकर गहमागहमी

"छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक शिकायती जांच पत्र को लेकर मंत्रालय में गहमागहमी है। लोगों की जुबान पर है कि रिटायर मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा बख्शे गए दागी IAS–IPS अधिकारियों के प्रति नए मुख्य सचिव आखिर नरमी बरतेंगे या फिर सख़्ती। दरअसल, नए मुख्य सचिव को ED का शिकायती पत्र विरासत में प्राप्त हुआ है। बताते हैं कि ED ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और ACB-EOW को पत्र लिखकर दागी अफसरों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने का फ़रमान जारी किया है। ED के इस पत्र में बताया गया है कि जांच के दौरान आरोपी सूर्यकांत तिवारी की डायरी में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेनदेन का ब्यौरा मिला था। इसकी जाँच पड़ताल के बाद अफसरों की कार्यप्रणाली आर्थिक अपराध के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक कोल माफिया सूर्यकान्त तिवारी की "डायरी" में दर्ज प्रभावशाली अधिकारियों का घोटालों से करीब का नाता और अवैध कारोबार सामने आया हैं। तस्दीक की जा रही है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इनमें 02 IPS और 02 IAS समेत 01 एडिशनल SP शामिल बताये जाते हैं। उनके बीच लेनदेन के ब्योरे में साफ़ किया गया है कि एक IPS अधिकारी ने सूर्यकांत तिवारी को 11.5 करोड़ सौंपे थे। जबकि ख़ुफ़िया जिम्मेदारी संभाल रहे एक ASP को आरोपी तिवारी ने 5.67 करोड़ की नगद रकम सौंपी थी। ED ने इस पत्र में यह भी बताया है कि डायरी में दर्ज लेन-देन की तारीख, राशि और पक्षों के नाम सहित पूरा ब्यौरा मय सबूत उसे प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ शासन को यह जानकारी भी साफ़ कर दी गई है कि दागी अफसर किस तरह से अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। ED ने इस संबंध में 5 प्रमुख अधिकारियों का आरोपियों से जुड़े लेन-देन का ब्योरा सामने रखा है। महासमुंद जिले में तैनात रहे एक अन्य आईपीएस अधिकारी ने भी सूर्यकान्त को 2.65 करोड़ की नगदी सौंपी थी। सूत्र तस्दीक करते हैं कि अवैध वसूली के एक प्रकरण में एक अन्य IAS अधिकारी ने 75 लाख की नगदी जबकि दूसरे आईएएस ने 60 करोड़ रुपए की नगदी आरोपी सूर्यकांत को सौंपी थी।

नये मुख्य सचिव की कार्यवाही पर सबकी नजर

फ़िलहाल, ED का पत्र मंत्रालय में भी चर्चा में है। केबिनेट के पूर्व इस पत्र पर वैधानिक कार्यवाही को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार की मंशा भी टटोली जा रही है। माना जा रहा है कि नए चीफ सेक्रेट्री पदभार ग्रहण करते ही दागी अफसरों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के लिए निर्देशित कर सकते हैं। दरअसल, प्रदेश में चीफ सेक्रेट्री ACB–EOW के पदेन मुखिया भी होते हैं। कोयला घोटाले मामले में ED की रिपोर्ट पर प्रदेश के ACB/EOW ने अब तक 2 पूर्व मंत्रियों, एक विधायक समेत 36 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की थी। इस मामले में IAS रानू साहू, IAS समीर विश्नोई, डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी का नाम मुख्य रूप से शामिल है। फ़िलहाल, मुख्यमंत्री साय केबिनेट की बैठक में नए चीफ सेक्रेट्री के स्वागत और पूर्व चीफ सेक्रेट्री की विदाई तय कार्यक्रम के तहत परवान चढ़ रही है। देखना गौरतलब होगा कि नए निजाम की छत्रछाया में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का आगाज़ किस तर्ज पर होता है?

नेपाल की क्रांतिः लोकतंत्र के लिए विनाशक

-विजया पाठक

नेपाल में हाल ही में हुई क्रांति लोकतंत्र के लिए विनाशक के रूप में है। नेपाल में तख्तापलट ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर अस्थिरता की चिंता पैदा कर दी है। इससे पहले हम श्रीलंका और बांग्लादेश में भी ऐसी ही क्रांति को देख चुके हैं। वहां पर कैसे सरकार को घुटनों पर ला दिया है। यह सभी देश भारत के पड़ोसी देश हैं और कहीं न कहीं इसका असर हमारे देश पर भी सामरिक रूप से पड़ता है। नेपाल के इतिहास में इसे बड़ी तख्तापलट की घटना के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसी तरह का जनआक्रोश फूट चुका है। वहां की सरकारें अपदस्थ हुई हैं। नेपाल छोटा हिमालयी राष्ट्र न केवल भारत और चीन के बीच रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का केंद्र भी है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन या अस्थिरता का सबसे अधिक फायदा किसे होगा। क्या यह बदलाव नेपाल के आंतरिक राजनीतिक संकट का परिणाम है या किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव? नेपाल, भारत और चीन के बीच स्थित है। उत्तर में चीन का तिब्बत क्षेत्र और दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में भारत की सीमाएं हैं। इसके अलावा नेपाल समुद्र तक पहुंच से वंचित है, इसलिए व्यापार और परिवहन के लिए भारत पर उसकी निर्भरता ऐतिहासिक रूप से अधिक रही है। वहीं, बीते कुछ वर्षों में चीन ने भी नेपाल में निवेश बढ़ाकर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है। नेपाल का भू-राजनीतिक महत्व इस बात में है कि यह हिमालयी क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार, जल संसाधन और रणनीतिक सहयोग का केंद्र बन सकता है। इसलिए कोई भी अस्थिरता क्षेत्रीय शक्तियों के हितों को प्रभावित कर सकती है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, सांस्कृतिक रिश्ते, व्यापार, ऊर्जा और जल संसाधनों पर साझा हित हैं। नेपाल में अस्थिरता से भारत को सबसे बड़ा खतरा सीमा पार से अवैध गतिविधियों, हथियारों की तस्करी और कट्टरपंथी विचारधाराओं के फैलाव का है। इसके अलावा, नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता से भारत के साथ चल रहे जल परियोजनाओं, व्यापार मार्गों और बुनियादी ढांचे के सहयोग पर असर पड़ सकता

है। हालाँकि, भारत की कूटनीतिक पकड़ मजबूत है। नेपाल में राजनीतिक संकट के दौरान भारत शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत कर सकता है। भारत की दीर्घकालीन नीति नेपाल को विकास साझेदार बनाने की रही है। इसके उलट, यदि भारत नेपाल को आर्थिक और राजनीतिक सहयोग देकर उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समर्थन देता है, तो यह भारत की साख को मजबूत कर सकता है।

चीन लंबे समय से नेपाल में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नेपाल में अस्थिरता चीन को निम्न लाभ दे सकती है। संकट के समय चीन आर्थिक सहायता, ऋण या निवेश देकर नेपाल के भीतर अपने समर्थक नेताओं को प्रोत्साहित कर सकता है। यदि नेपाल चीन की ओर झुकता है तो वह हिमालय क्षेत्र में चीन के व्यापार और सुरक्षा हितों को मजबूती देगा। नेपाल में चीन समर्थक सरकार आने से भारत की परंपरागत भूमिका चुनौती में पड़ सकती है। चीन जल विद्युत, आधारभूत संरचना, सड़क और संचार क्षेत्र में निवेश कर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है।

नेपाल में अस्थिरता से अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतों की चिंता भी बढ़ सकती है। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में नेपाल के साथ सहयोग करना चाहेंगे। परंतु उनकी पहुँच सीमित है; नेपाल में निवेश या प्रभाव बढ़ाने में भारत और चीन जैसी पड़ोसी शक्तियों की भूमिका ही प्रमुख रहती है। नेपाल में तख्तापलट से सबसे अधिक फायदा चीन को हो सकता है, जो संकट का लाभ उठाकर अपने आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाना चाहेगा। भारत को सतर्क रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हुए नेपाल की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। अन्य अंतरराष्ट्रीय शक्तियाँ भी सहयोग कर सकती हैं, परंतु भौगोलिक समीकरणों के कारण दक्षिण एशिया में भारत और चीन की भूमिका सबसे निर्णायक बनी रहेगी। नेपाल की स्थिरता क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संपर्क के लिए आवश्यक है। यही इस संकट का सबसे बड़ा सबक है।

17 साल के गैर राजतांत्रिक नेपाल में 15 सरकारें तो बदलीं, परंतु हालात नहीं बदले। इसी बीच राजशाही और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगे भी उठती रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से जनता को पता चला कि मंत्री और उनके परिजन देश-विदेश में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे विदेशों में अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। ब्रांडेड सामान के साथ फाइव स्टार जीवन विदेशों में व्यतीत कर रहे हैं। इस वैभव की पृष्ठभूमि में सरकारी स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को मुख्य कारण माना। जबकि गरीब युवा प्रतिदिन तीन हजार से ज्यादा की संख्या में पलायन करने को विवश हो रहे हैं। इस आंदोलन को पहले दक्षिणपंथी करार देने की कोशिशें हुईं, लेकिन वास्तव में यह आक्रोश उस कुंठा के चलते उपजा जो नेताओं और उनके परिजनों के वीडियों में भोग-विलास का जीवन जीते हुए दिखा।

नेपाल में हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। वहां अनेक संगठन सड़कों पर उतरकर राजशाही के पक्ष में आंदोलन कर चुके हैं। इस मांग में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शामिल रही हैं। इस मांग को मुख्य रूप से राष्ट्रवादी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी कर रही है। नेपाल को 2007 में पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। नतीजतन 2008 में राजशाही व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। 2008 में नेपाल के गणराज्य बनने के बाद से कारोबारी दुर्गा प्रसाई आंदोलन को हवा दे रहे हैं। एक समय प्रसाई के प्रधानमंत्री प्रचंड और ओली के साथ घनिष्ट संबंध थे, लेकिन बाद में वे दोनों के आलोचक हो गए। इसी समय राजशाही के दौर में गृहमंत्री रहे कमल थापा ने हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए नया गठबंधन बना लिया है। पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह भी एकाएक सक्रिय होकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी करने लगे हैं। वह मंदिरों में होने वाली पूजा में शामिल हो रहे हैं।

नेपाल की 85.5 प्रतिशत आबादी हिंदू है, इसलिए वह प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी देश है। नेपाल में लंबे समय तक राजशाही रही है। किंतु राजशाही के खूनी दुखद अंत के बाद यहां माओवादी नेता प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने से सामंतशाही सिमटती चली गई और 18 मई 2006 को राजा के अधिकारों में कटौती कर नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर माओवादी लोकतंत्र की शुरूआत हो गई। तभी से चीनी हस्तक्षेप के चलते यहां के मूल स्वरूप को बदलने के अलावा भारत के साथ संबंध खराब होने की शुरुआत भी हो गई थी। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री रहते हुए चीन के दबाव में न केवल भारत से शत्रुतापूर्ण संबंधों की बुनियाद रखी थी, बल्कि चीनी सेना को खुली छूट देकर अपनी जमीन भी खोना शुरू कर दी। जाहिर है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना तो हो गई, लेकिन लचर नेतृत्व के चलते यह देश अपना अस्तित्व खोने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। इसी चिंता से यह आक्रोश उपजा है। हमारे पड़ोसी देशों में नेपाल और भूटान ऐसे देश हैं, जिनके साथ हमारे संबंध विश्वास और स्थिरता के रहे हैं। यही वजह है कि भारत और नेपाल के बीच 1950 में हुई सुलह, शांति और दोस्ती की संधि आज भी कायम है। नेपाल और भूटान से जुड़ी 1850 किमी लंबी सीमा रेखा बिना किसी पुख्ता पहरेदारी के खुली है। बावजूद चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह कोई ठोस विवाद नहीं है। बिना पारपत्र के आवाजाही निरंतर जारी है। करीब 60 लाख नेपाली भारत में काम करके रोजी-रोटी कमा रहे हैं। 3000 नेपाली छात्रों को भारत हर साल छात्रवृत्ति देता है। नेपाल के विदेशी निवेश में भी अब तक का सबसे बड़ा 47 प्रतिशत हिस्सा भारत का है। बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेपाल का झुकाव चीन की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2014 में नेपाल की यात्रा करके बिगड़ते संबंधों को आत्मीय बनाने की सार्थक पहल की थी, किंतु भारतीय मूल के मधेषियों के आंदोलन ने इस पर पानी फेर दिया था।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में व्यस्त

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. देवरीकला। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय निकायों और पंचायतों को फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2025 के पर्यवेक्षण के लिए आयोग द्वारा आर कामनकर को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक कामनकर 14 से 19 अक्टूबर तक हरदा जिले के प्रवास पर रहेंगे। इसलिए टिमरनी विकासखंड में समस्त बीएलओ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में व्यस्त हैं। सबसे ज्यादा बीएलओ का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जिम्मे है जिसे यह लोग बहुत ही सतर्कता और नियमानुसार पूर्ण करने में लगे हुए हैं। देखने में आता है कि मातृशक्ति जिस भी विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत है वह पूर्ण ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करती हैं। नगर टिमरनी में भी नगर परिषद कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी

कार्यकर्ताओं को बीएलओ के पद का निर्वहन करते देखा जा रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव व रोजगार सहायक भी लगे हुए हैं। मतदाता सूची के कार्य में लगे होने से इनका मूल कार्य प्रभावित होता है क्योंकि ये लोग सीधे जमीन से जुड़े कर्मचारी हैं, आम जनता को किसी कार्य हेतु पहले इन कर्मचारियों से ही मिलना होता है। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य हेतु अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था करना चाहिए।

वायरल ऑडियो से हड़कंप, युवक ने कलेक्टर-एसपी को दी चुनौती, शराब बेचने से कोई नहीं रोक सकता

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. सागर। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो क्लिप बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस और प्रशासन के बीच हड़कंप मचा दिया है। इस ऑडियो में एक युवक, जो कथित तौर पर महात्मा गांधी की वेशभूषा रहता है, जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सीधे चुनौती दे रहा है। युवक ऑडियो में बेहद आक्रामक अंदाज में दावा कर रहा है कि उसे शराब बेचने से कोई नहीं रोक सकता। ऑडियो के अनुसार, वह कहता है कि "जब तक लोग सो कर उठते हैं, उतने में भी शराब लेकर चले जाते हैं पीने वाले।" यह बयान जिले में अवैध शराब बिक्री के खुलेआम चलन की ओर इशारा करता है और साथ ही प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह वायरल ऑडियो क्लिप ऐसे समय में सामने आया है जब पुलिस प्रशासन अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने का दावा कर रहा है। गांधी की वेशभूषा में इस तरह की चुनौती देने का मामला न केवल कानून व्यवस्था के लिए, बल्कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिहाज से भी गंभीर माना जा रहा है।

गौरवशाली 25 वर्ष

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

हमर छत्तीसगढ़

विकास और विश्वास का नया दौर

स्वास्थ्य

सन् 2000

- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.585
- शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर 77
- ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा कमजोर
- जिला अस्पतालों की संख्या 06

सन् 2025

- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.672
- शिशु मृत्यु दर: प्रति हजार जीवित जन्म पर 38
- ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
- जिला अस्पतालों की संख्या 30

QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

R.O. No. : 13456/ 1

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)